

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

C Govt. of Haryana

No. 77-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 4, 2020 (JYAISTHA 14, 1942 SAKA)

#### हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 4 जून, 2020

संख्या 4/71—2019 पैंशन—II(1).— हरियाणा सम्बद्ध अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को कार्य नियमों 1977 के नियम—15 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, "पं० दीनदयाल उपाध्याय मानदेय स्कीम" दिनांक 01.01.2019 से लागू करतें है जो दिनांक 28.07.1988 से 10.05.1998 के दौरान अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षक / गैर शिक्षक वर्ग से सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों पर निम्नलिखित दर / नियम तथा शर्तों के आधार पर लागू होगी:—

क्रमांक नं0	श्रेणी	म नदेय राशि प्रति मास
1.	प्राचार्य .	20,000 / - रूपये
2.	मुख्याध्यापक	18,000 / - रूपये
3.	प्राध्यापक	16,000 / - रूपरो
4.	अध्यापक / हिन्दी / पंजाबी / संस्कृत / उर्दू अध्यापक	14,000 / - रूपये
5.	जे०बी०टी० / कला अध्यापक / पी०टी०आई० / कटिंग एंड टेलरिंग अध्यापक	12,000 / - रूपये
6.	नॉन-टीचिंग स्टाफ (तृतीय श्रेणी)	11,000 / - रूपये
7.	नॉन-टीचिंग स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी)	6,000 / - रूपये

- 1. जो कर्मचारी अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से दिनांक 28.07.1988 से 10.05.1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत हुये है तथा दिनांक 01.01.2019 को जीवित है उन्हे ही प्राप्त बजट में वर्ष 2020—21 के प्रावधान के अन्तर्गत मानदेय की राशि बतौर पेंशन प्रदान की जायेगी।
- 4. जो अधिकारी / कर्मचारी सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्य करते हुये सेवानिवृत हुये है उन्हें यह लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा 10 वर्ष की योग्य सेवा सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध की है उन्हे यह लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 4. सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी स्तर पर उक्त लाभ के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
- 5. सेवानिवृत कर्मचारी केवल निर्धारित मानदेय की राशि का हकदार होगा जो उसे एकमुश्त अथवा मासिक तौर पर प्रदान की जायेगी तथा इस राशि पर मंहगाई भत्ता व अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- 6. जिन सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28.07.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया है वह मानदेय के हकदार नहीं होंगे।

- 7. यह राशि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा निकाली जाएगी तथा सेवानिवृत कर्मचारी को उसके बैंक खाते में प्रत्येक मास की 7 तारीख तक जमा करवा दी जाएगी। तत्पश्चात सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक मास के द्वितीय सप्ताह तक निदेशालय की सम्बन्धित पैंशन शाखा को राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जायेगा।
- मानदेय की राशि का भुगतान सेवानिवृत कर्मचारी के मृत्यु होने तक किया जायेगा तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित एवं कानूनी हकदार को यह राशि देय नहीं होगी।
- मानदेय राशि का भुगतान उन्ही सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदान किया जायेगा जो किसी अन्य स्त्रोत र सेवानिवृत पँशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहें है। यदि यह पाया गया कि मानदेय प्राप्तकर्ता किसी अन्य प्रकार का लाभ पैंशन के रूप में प्राप्त कर रहा है तो यह राशि तुरन्त प्रभाव से रोक दी जायेगी तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि पाने वाले से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूली जायेगी।
- 10. यह स्कीम 01.01.2019 से प्रभावी होगी तथा अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से दिनांक 28.07.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार मानदेय राशि प्रदान की जायेगी।
- 11. योग्य सेवानिवृत कर्मचारियों को अपने आवेदन शपथ पत्र सहित उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लेख करते हुए मानदेय प्रदान करने के लिए सम्बन्धित अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रंबंधन को प्रस्तुत करेगा तथा वे उसे दो दिन के अंदर—अंदर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को रिफारिश सहित अग्रेषित करेंगे। आगे की कार्यवाही के लिए वे उसे सम्बन्धित निदेशालय को भेजेंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पैंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम 2001 के तहत निरीक्षण उपरान्त मानदेय प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- 12. यदि किसी सेवानिवृत कर्मचारी का देहान्त हो जाता है तो उस मामले में उसके मानदेय के ऐरियर का भुगतान मृतक कर्मचारी के वैध पति / पत्नी / कानूनी उतराधिकारी जैसी भी स्थिति हो, तो सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु तिथि तक देय
  - यह राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वहन होगी:-
  - "The amount shall be charged/debitable to the major Head "The charges will debitable to the Head "2202-General Education-02-Secondary Education-110-Assistance to Non-Governments Secondary Schools 96-introduction of pension scheme for Non-Govt. Aided Secondary Schools 09 Grant in Aid-General".

वित्त विभाग की सहमति उनके U.O. No. 2/13/2006-4 FD-II/36564 दिनांक 24.01.2020 के अंतर्गत प्राप्त की गई है।

डॉ॰ महावीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

### HARYANA GOVERNMENT

## SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

## Notification

The 4th June, 2020

No. 4/71-2019 Pension-II (1).— The Governor of Haryana is pleased for implementation of this scheme may be called "Pt. Deen Dayal Upadhyaya Honorarium Scheme" for the teaching/non-teaching employees w.e.f. mentioned below and as per the terms & conditions:-

Sr. No.	Category of retirees	Rate of Honorarium per month	
1.	*Principal	Rs. 20,000/-	
2.	Headmaster	Rs. 18,000/-	
3.	Lecturers	Rs. 16,000/-	
4.	Masters/Hindi/Punjabi/Sanskrit/Urdu Teachers	Rs. 14,000/-	
5.	JBTs/Drawing Teachers/PTIs/Cutting & Tailoring Teachers etc.		

ßr. No.	Category of retirees	Rate of Honorarium per month
6.	Non-Teaching Staff (Class III)	Rs. 11,000/-
7.	Non-Teaching Staff (Class IV)	Rs. 6,000/-

Terms and conditions for grant of honorarium:-

- The expenditure will be incurred within existing budget provision on account of honorarium in the shape of pension to the retirees of aided schools, who retired from 28.07.1988 to 10.05.1998, and who are still alive on the date of 01.01.2019.
- These retirees should have worked against the sanctioned/aided posts and retired as such from the privately managed aided schools of the State of Haryana.
- 3 They must have fulfilled the conditions of minimum qualifying service of 10 years on sanctioned/ aided post at the time of their retirement from such schools.
- 4. That in case of death of any retiree, the dependents of the retiree will not be entitled for this benefit at any stage in any circumstances.
- 5. These retirees will be entitled only for fixed amount of honorarium, which will be given on monthly basis and no DA and other allowances will be admissible to these retirees on this fixed amount.
- 6. Those retirees, who had resigned from the service on any ground during their service tenure i.e. w.e.f. 28.07.1988 to 10.05.1998, will not be entitled for honorarium.
- 7. The amount will be drawn at the level of concerned District Education Officer/District Elementary Education Officer and will be disbursed to the respective retirees in their respective Bank Accounts latest by 7th of every month. Thereafter, the concerned District Education Officer/District Elementary Education Officer will send the Utilization Certificate relating to their district to the Pension Branch of the respective Directorates by the 2nd week of each month.
- 8. The honorarium shall be paid till the death of the retiree and it shall not be extended to any dependents or legal heir of the retirees on any grounds.
- The honorarium will be granted only to those retirees, who are not getting any other such type of pension benefits. In case, it is found that he/she is receiving any other kind of pension then this honorarium will be stopped with immediate effect and will be liable to refund such paid amount of honorarium from the receiver with interest @ 10% per annum.
- 10. This policy shall come into force w.e.f. the date of 01.01.2019. Thus, the only such employees who were working on sanctioned/aided posts in the Privately Managed Aided Schools Retired between 28.07.1988 to 10.05.1998 will be entitled for honorarium as mentioned above.
- The eligible retiree will have to submit an application along with an affidavit by mentioning the above terms & conditions for grant of honorarium to the concerned Management of privately managed aided school and the same will be forwarded by them within two days to the concerned District Education Officer/District Elementary Education Officer with their recommendations. Further, the same will be sent to the concerned Directorates by them. After examination of the same by the competent authority, as defined in Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund), Rules, 2001 necessary order for grant of honorarium will be issued.
- 12. In case of any retiree happen to demise in that case arrears of honorarium will be granted to the legitimate spouse/legal heir's as the case may be, till his/her death.

"The amount shall be charged/debitable to the major Head "The charges will debitable to the Head "2202-General Education-02-Secondary Education-110-Assistance to Non-Governments Secondary Schools 96-introduction of pension scheme for Non-Govt. Aided Secondary Schools 09 Grant in Aid-General".

The concurrence of the Finance Department have been obtained *vide* their U.O. No. 2/13/2006-1 FD-II/36564 dated 24.01.2020.

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department, Chandigarh.

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, School Education Department, Chandigarh.

To

- The Director General Secondary Education, Haryana
- The Director Elementary Education, Haryana 2. Panchkula

Memo No. 4/16-2017 Pen-II(2) Dated, Chandigarh, the

Revision of Pension/Family Pension/Enhanced Family Pension and Subject:-Death-Cum-retirement Gratuity for the retirees of Privately Managed Government Aided-Schools consequent upon the recommendations of 7th Pay Commission with effect from 01-01-2016.

Refer to the subject cited above.

In exercise of the powers conferred upon Government under rule 23 of Haryana Aided-School (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001 the Governor of the Haryana is pleased to introduce following modifications in the rules regulating Pension, Family Pension, Enhanced Family Pension and Death-Cum-Retirement Gratuity for the retirees of Privately Managed Government Aided-Schools in the State in accordance with the recommendations of 7th Pay Commission as applicable to State of Haryana with effect from 01.01.2016.

# REVISION OF PENSION OF TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES RETIRED PRIOR TO 01.01.2016:

## Consolidation of Pension/Family Pension:-

(1) The entitlement of pension/family pension of existing pre- Jan.2016 pensioners/family pensioners will be consolidated to be effective with effect from 1.1.2016 by adding together:-

> From 01.01.2016, the re-calculation formula will be Basic Pension X 2.57 of Basic Pension/Family Pension.

> Provided that minimum pension/family pension is no case be less than Rs.9000/- p.m. w.e.f. 01.01.2016.

- The minimum pension/family pension w.e.f the 1st January, 2016 shall be Rs. 9,000/- p.m. The maximum pension shall be Rs.1,12,050 i.e. 50% and family pension Rs.67,230/- i.e. 30% of the highest pay i.e. Rs.2,24,100/- in the Government of Haryana. Pro-rata of Pension/Family Pension.
- The requirement of minimum service shall be considered under the provisions of rules applicable at the time of retirement/death of the employee. The amount so arrived at will be regarded as consolidated pension/family pension with effect from 01.01.2016.

## REVISION OF PENSION OF TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES RETIRED ON OR AFTER 01.01.2016:

Revised provision for calculation of pension/family pension: (1) Linkage of full pension with 28 years of qualifying service shall be

modified to the extent that once an employee retires after rendering the

minimum qualifying service of 20 years, pension shall be sanctioned at 50 percent of the emoluments subject to other conditions regulating the same.

(2) In all such cases where employee becomes entitled to pension on superannuation after completion of 10 years of qualifying service pension shall be calculated on proportionate basis to the amount of full pension admissible to him;

The calculation of ratio of proportionate admissibility of the pension in all such cases where the said qualifying period of full pension benefits have been so reduced to 20 years shall be made in the manner specified below:-

(i) In cases of qualifying service being 20 years or above: last pay drawnX40/40X2.
(ii) In cases where the actual qualifying service falls short of 20 years but happens to be more than 10 years: Last Pay Drawn X 'Number of qualifying service in half years (HY)/40X2 i.e. 30 HY/40X2 or 36 HY/40X2 etc.

## Minimum and maximum ceiling of pension/family pension.

3. The amount of pension shall be subject to a minimum of Rs.9000/- with effect from 1st January, 2016 and maximum upto 50 percent of highest pay in the Government. The highest pay in Haryana Government is Rs.2,24100/- with effect from 1st January, 2016.

#### 4. DCRG:

- (1) The maximum limit of death-cum-retirement gratuity shall be Rs. 20.00 Lakh who retires on or after 1.1.2016. This rule does not reduce the qualifying service for availing the full benefit of DCRG and only enhances the limits and, therefore, the qualifying service for availing the full benefit here would continue to be thirty-three years (or thirty-five years for Group-D employees).
  - (2) Emoluments means.

As on 01.01.2016: Basic Pay in the Pay Matrix + DA as applicable from time to time.

The eligibility condition of the pension/family Pension/DCRG in the existing Pension Rules namely Haryana Aided Schools (Special Pension & Contributory Provident Fund) Rules, 2001 (Amended) shall remains the same.

### Arrears

The arrear of pension/family pension and DCRG shall commence from 01.01.2016.

This issue with the concurrence of Finance Department conveyed vide their UO No.78/12/2018-3FDII/32497 dated 30.01.2019.

Special Secretary School Education
For Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh

13/2/15

Endst. No. 4/16-2017 Pen-II (2)

Dated, Panchkula the

A copy of the above is forwarded to the following for information and

necessary action:-

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.

2. The Accountant General (Audit), Haryana Chandigarh.

3. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Finance Department, Chandigarh with reference to their U.O. No. 78/12/2018-3 FDII/32497 dated 30.01.2019.

4. All District Education Officer, in the Haryana State.

5. All District Elementary Education Officer, in the Haryana State.

6. All the Principal/Manager, Government Aided Schools in the Haryana State. 7. All Associations of retired schools teaching and non-teaching employees in

the State of Haryana.

8. Senior Account Officer Pension-II Br. (Local).

9. PS/Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, School Education Department, Chandigarh.

10.PS/Director General Secondary Education, Haryana, Panchkula.

11.PA/Director Elementary Education, Haryana, Panchkula.

12. Assistants I & IV (Pension-II) Local.

13. Superintendent, Aided School Br. (Local). 14. Additional Director Admn/Joint Director Admn/Deputy Director (IT Cell).

> Special Secretary School Education For Additional Chief Secretary to Govt. Haryana School Education Department Chandigarh

Regd.

The Director Secondary Education, Haryana Shiksha Sadan Sector-5, Panchkula

All the DEOs/ DEEOs in the State.

Memo No. 8/12-2015 Pension-II (4)
Dated Panchkula the

Subject: -

Clarification to grant benefits of intervening period to the employees of Aided Schools as per Haryana School Education (Amendment) Rules 2007.

In refer to the subject cited above.

Sh. Ishwar Singh, P.T.I. (Retd.), S.D. High School, Lakhan Majra (Rohtak) had riled CWP No. 7684 of 2015 titled as Ishwar Singh V/s State of Haryana and others in Hon'ble Punjah & Haryana High Court, Chandigarh praying therein to direct the respondent to allow petitioner pension & pensionary benefits by taking into consideration the service rendered by him w.e.f. 18.01.1988 to 31.10.2011 i.e. 23 years 09 months and 14 days as petitioner had deposited the contributory share of Provident Fund qua Management share alongwith interest but respondents vide PPO dated 04.12.2014 (P-1) allowed him the pension for 13 years 06 months only and further prayed that the Respondents may also be directed to revise the pension and pensionary benefits of the petitioner after computing the service w.e.f. 18.01.1988 to 31.10.2011 and release the difference between due and drawn of the retiral benefits like pension, gratuity, commutation and leave encashment etc. alongwith interest @ 18% per annum.

The matter was listed before the Hon'ble Court on 09.08.2016 and the Hon'ble High Court was pleased to pass the following orders:-

"As such, the present writ petition is allowed and a writ of mandamus is issued directing the rest ondents to compute the qualifying period of the petitioner for pension and pensionary benefits from 18.1.1988 to 31.10.2011 i.e. 23 years 9 months and 14 days and grant the pension and pensionary benefits like pension, gratuity, commutation, leave encashment accordingly. Arrears shall carry interest @ 9% per annum starting three months after the date he deposited his remaining share of CPF alongwith interest amounting to

After passing the above order the matter was referred to Learned LR and Advocate General, Haryana for opinion by the department. Thereafter, the Learned LR and Advocate General, Haryana has opined that it is not a fit case for filing LPA and the department have to implement the order dated 09.08.2016 passed by Hon'ble High Court in CWP No. 7684 of 2015 titled as Ishwar Singh Vs. State of Haryana & others by counting the above intervening period as qualifying service for the purpose of pensionary benefits after depositing the CPF contributio 1 by the employee and employer share.

In this regard, it is stated that there is a following provision in Rule 114 of Haryana School Education Rules 2003:-

114. The provisions contained in this chapter shall apply to all employees working on the sanctioned aided posts in the aided school, The said provisions shall not apply to the employees appointed on probation on permanent post in an aided school unless they complete their probation period successfully. After the completion of the period of probation successfully they shall have the option to subscribe to the fund for the probation period also.

Further, Haryana School Education Rules 2003 were amended vide notification dated 19.01.2007 and amended Rules namely Haryana School Education (Amendment) Rules 2007 came into force w.e.f. 01.04.2007 and vide rule 32 in rule 114 of the aforesaid Rules, the following provision has been made:-

- 32. In the said rules, in rule 114,-
  - (i) for sign "." existing at the end, the sign "." shall be substituted;
  - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the employee/ retiree who has not availed of the option till now, may give fresh option to deposit the subscription to fund alongwith interest at the prevailing rate as worked out by Director within 90 days from the date of commencement of these rules."

However, the petitioner, Sh. Ishwar Singh had submitted his option within the stipulated period as required in the aforesaid rule i.e. within 90 days upto 30.06.2007. Hence, the benefit of probation period i.e. two years which can be extended for one more year i.e. maximum three years can be extended to him as qualifying service for the purpose of pensionary benefits. However, in case of a Govt. employee, as per their service rules/instructions the period of probation period is only maximum two years.

In the instant case, the probation period of the petitioner was from 18.01.1988 to 18.01.1990 for which he has already been given option for deduction of CPP contribution in terms of ibid rule. Although, there is ambiguity regarding counting of his service from 19.01.1990 to 30.04.1998 as qualifying service for the purpose of pensionary benefits, as the petitioner could not subscribe toward CPF deduction for that period. In fact he had started to contribute towards CPF w.e.f. 01.05.1998 to the date of superannuation i.e. 31.10.2011.

It has been also observed by the department that there are so many similar cases for example, Mr. 'X' was appointed on sanctioned/aided post in any aided school on 01.04.1970 and completed probationary period on 31.03.1973. He has started to deposit CPF contribution w.e.f. 01.05.1980 till his retirement on 31.05.2010. He has been allowed by the department to count his period of probation towards pensionary benefit as aqualifying service i.e. 01.04.1970 to 31.03.1973. But he was not granted the benefit of his

benefits. Whereas, he has been allowed the benefit of higher standard scale by counting the period as qualifying service. There is a total confusion on this issue as to why the said employee is being deprived of this period as qualifying service of the purpose of pensionary benefits in case he is ready to deposit the CPF contribution alongwith prevailing rate of interest from 01.04.1973 to 30.04.1980.

In view of the position explained above, therefore, it has been decided by the Government vide order dated 08.03.2017 to extend the benefits of the intervening period as qualifying service for the purpose of pensionary benefits i.e. from the date of first appointment of any employee on sanctioned/aided posts in any Govt. Aided schools till the actual date of their subscription toward CPF deduction subject to the condition that the said employees have to deposit their CPF share alongwith interest on prevailing rates into Govt. account, if they had opted fresh option within the stipulated period i.e. 30.06.2007 as sought by amending the ibid Rules on 19.01.2007.

Note:- You are requested to convey all the managements of the aided schools in your district.

\*

Deputy Director Pension-II For Director Secondary Education Haryana Panchkula